YOUNG RESEARCH FORUM
Lakshmibai college

TITLE - IMPACT OF CORONA EPIDEMIC ON EDUCATION
Project No: LBC/YRF/2021/012
Year Of Submission : 2020-21

Mentees -1.**Subia Noor**
(B.A Hons political Science, 4th sem, 432)
2.**Rubia Noor**
(B.A Hons political science, 4th sem, 281)
3.**Sujeeta**
(B.A program, 6th sem, 1388)

Mentors- 1.**Sangita Sharma**
Asst. professor
Lakshmibai college
2.**Sonia Dabas**
Asso. professor
Lakshmibai College

पाठ - 1

- सार

आज संपूर्ण विश्व कोरोना नामक अदृश्य वायरस का सामना कर रहा है जिसने पूरे मानव समुदाय के जीवन पर व्यापक प्रभाव डाला है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तथा सामाजिक दूरी को बनाए रखने के उद्देश्य से ही भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी जिसके चलते वर्तमान समय में छोटी से लेकर बड़ी औद्योगिक इकाइयां, दुकान, रेस्टोरेंट के साथ-साथ सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद करने पड़े। इसका स्वभाविक रूप से शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक संस्थान बंद होने से विश्व की तकरीबन 94% छात्र आबादी प्रभावित हुई है तथा निम्न मध्यवर्गीय आय वाले देशों में यह संख्या 99% है। यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोरोना वायरस के दौर में जहां एक ओर भारत ने डिजिटलाइजेशन के एक नए युग में प्रवेश किया है तथा छात्रों की तकनीकी समझ बड़ी है वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन माध्यमों के अभाव में एक बहुत बड़े विद्यार्थी वर्ग के स्कूली शिक्षा से बिछड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है तथा आर्थिक असमानता, लैंगिक असमानता ,कुपोषण, बाल श्रम आदि समस्याओं ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। इस शोध अध्ययन में मुख्य रूप से भारत में कोरोना वायरस के स्कूली शिक्षा पर पड़ने वाले सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों का विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन किया

गया है एवं सर्वे व प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से वर्तमान ऑनलाइन शिक्षा के युग में छात्रों के समक्ष आने वाली मुख्य समस्याओं को समझने की चेष्टा की गई है। साथ ही स्कूली शिक्षा व्यवस्था में मौजूदा विभिन्न चुनौतियां को दूर करने के उपाय भी सुझाए गए हैं।

मुख्य शब्द - डिजिटलाइजेशन,तकनीकी समझ, स्कूली शिक्षा, आर्थिक असमानता, कुपोषण, विश्लेषणात्मक अध्ययन ।

पाठ - 2

- ## परिचय

"सच्ची शिक्षा, छात्र छात्राओं के अंदर सर्वोत्तम सृजनशीलता का विकास करती है। विद्यार्थियों के मन मे अवांछित एवं अव्यवस्थित सूचना भर देने मात्र से ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह सब एक निष्प्राण भारी बोझ बन जाता हैं जो उनकी समग्र मौलिकता को कुचल देता हैं व उन्हे महज यंत्रवत बना देता हैं" ।

- महात्मा गांधी जी

इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि शिक्षा ने सदैव व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में आज मनुष्य शिक्षा के बलबूते ही सभ्यता के ऊँचे शिखर पर पहुँच पाया है। शिक्षा मनुष्य को असत्य से सत्य की ओर,अज्ञान से ज्ञान की ओर ,अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित तथा निर्देशित करती है। प्लेटो जी ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि शिक्षा उस प्रशिक्षण को कहेंगे जो बच्चो मे उचित आदते उत्पन्न कर सद्गुओं का विकास कर सके। वास्तव में शिक्षा नागरिकों के चरित्र का निर्माण करती है तथा समाज मे एक सृजनशील व्यक्ति के रूप मे उसे अपनी भूमिका का निर्वाह करने में सहायता करती है तथा नागरिको से ही समाज बनता है। इस प्रकार शिक्षा न केवल व्यक्ति विशेष के भविष्य को संवारने का काम करती है अपितु किसी भी समाज तथा देश के भविष्य निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती है। वास्तव में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है परंतु यह भी तथ्य है कि वर्तमान समय मे हम सभी एक ऐसी महामारी से जूझ रहे है जिसका इतिहास मे कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। 21 वी सदी की सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आई इस कोरोना नामक महामारी ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था व स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रहार किया है अपितु किसी भी देश की रीढ़ समझे जाने वाले शिक्षा क्षेत्र को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य मे देखे तो भारत मे कोरोना के बढ़ते कहर के कारण पिछले 15 महीनों से विद्यालय बंद है जिस कारण विद्यार्थी जीवन में काफी उथल पुथल हो गई है व उनकी शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ा है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण 15 लाख स्कूल बंद है जिससे 88 करोड़ 80 लाख छात्रों की पढ़ाई में गतिरोध उत्पन्न हुआ है तथा यह चौंकाने वाला तथ्य है कि इनमें से 27 करोड़ 70 लाख केवल भारत के बच्चे है। हम सभी इस बात से भली-भांति परिचित है कि प्राचीन भारत में गुरुकुल आधारित शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। शिक्षा के इस प्रारूप में पठन पाठन आश्रम के खुले प्रांगण में होता था। कालांतर मे गुरुकुल की जगह विद्यालयों ने ले ली तथा बच्चे ज्ञान अर्जित करने हेतु विद्यालयों मे जाने

लगे। विद्यालयों में जाकर जहां एक ओर बच्चों में सोचने समझने की समझ विकसित होती है वही दूसरी ओर उनमें नैतिक गुणों का भी समावेश होता है परंतु इस कोरोना काल मे जब सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है तो ऐसे मे बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, उन्हें उस स्तर का ज्ञानार्जन कैसे होगा जो विद्यालयों मे जाकर होता था,क्या ऑनलाइन माध्यम विद्यालयों का स्थान ले पाएंगे तथा ऑनलाइन माध्यमों के अभाव मे हमारे देश का भविष्य स्वयं अपना भविष्य कैसे उज्ज्वल कर पाएंगे, यह सभी प्रश्न हमारे सामने विद्यमान है जिनका जवाब भविष्य की गर्त मे छुपा हुआ है।

पाठ - 3

- ## उद्देश्य
- शिक्षा के क्षेत्र में नव- परिवर्तनशील शोध करना।
- कोरोना काल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न हुई बधाओ का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
- शैक्षणिक क्षेत्र में बढ़ती लैंगिक असमानता व आर्थिक असमानता पर गंभीर चिंतन करना।
- महामारी के दौर में शिक्षा क्षेत्र में आई चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करना।
- ऑनलाइन शिक्षा के लाभ -दोषो को तुलनात्मक अध्ययन करना।
- शिक्षा को सभी विधार्थियो तक पहुंचाने के आयामों की खोज करना।

पाठ - 4

- ## साहित्य की समीक्षा

प्रस्तावित शोध अध्ययन को करने से पहले हमने प्रस्तुत विषय पर पूर्व में प्रस्तुत किए गए विभिन्न शोध पत्रो, जर्नल्स,रिपोर्टो तथा स्टडीज का गहन अध्ययन किया जो इस प्रकार है →

ह्यूमन राइट्स वॉच की 17 मई 2021 को प्रकाशित 125 पृष्ठों की रिपोर्ट "वक़्त सालो तक इंतजार नही करता, कोविड 19 के कारण बच्चों के शिक्षा के अधिकार में असमानता मे वृद्धि " में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि विद्यालयों के बंद होने से बच्चे असमान रूप से प्रभावित हुए है क्योंकि महामारी के दौरान में सभी बच्चों के पास सिखने के लिए जरूरी अवसर, साधन या पहुंच नहीं हो पाई। साथ ही इस रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर किया गया कि कोरोना काल मे सरकारो के पास ऑनलाइन शिक्षा आरंभ करने के लिए ऐसी नीतियाँ, संसाधन या ढाँचा नहीं था कि सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा हासिल कर सके। इसे देखते हुए ह्यूमन राइट्स वॉच की वरिष्ठ एजुकेशन रिसर्चर एलिन मार्टिनेज ने कहा कि महामारी के दौरान लाखो बच्चों के शिक्षा से वंचित होने के कारण अब समय आ गया है कि बेहतर व अधिक न्यायापूर्ण शिक्षा प्रणाली का पुननिर्माण कर शिक्षा के अधिकार को सुदृढ़ किया जाए।

प्रीति तारकरी ने भी अपने शोध पत्र "शिक्षा प्रणाली पर कोविड 19 का प्रभाव" International Journal of Advanced science and technology 29 (95) 3812-3814,2020 मे कोरोना महामारी के शिक्षा पर पड़े प्रतिकूल प्रभावों की विस्तृत चर्चा की।

इस शोध पत्र में कहा गया कि शैक्षणिक संस्थान बंद होने से जहां एक ओर शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई वही छात्रों के समान्य दैनिक जीवन मे भी व्यवधान उत्पन्न हो गया। साथ ही शिक्षण पद्धति में ऑफलाइन से ऑनलाइन पढ़ाई में आए परिवर्तन के कारण छात्रो, शिक्षको, अभिभावको के साथ - साथ शिक्षा प्रणाली से संबंधित नीति बनाने मे नीति निर्माताओ को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अमिया कुमार मोहापात्रा ने भी अपने संपादकीय "कोविड 19 का शिक्षा पर प्रभाव" Journal of Management & Public policy VOL NO.2,June 2020 मे यह तथ्य उजागर किया कि शिक्षा क्षेत्र को कोरोना महामारी के बीच अस्तित्व की जबरदस्त चुनौती का सामना करना पड़ा है। वर्तमान समय में रियल टाइम लर्निंग बेतरतीब ढंग से बंद हो गई है तथा जहां ऑनलाइन कक्षा व सत्रों में भाग लेने से छात्र अत्यधिक तनाव में हैं वहीं अपनी परीक्षाओं को लेकर भी वह संशय में हैं। साथ ही इस शोध पत्र में यह भी कहा गया कि एजुकेशन लोन लेकर अपनी पढ़ाई जारी रखने वाले छात्रों को कोरोना काल में विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति मे सरकार को शिक्षा ऋण के मामले में विद्यार्थियों के हित में आवश्यक कदम उठाने चाहिए तथा ऑनलाइन लर्निंग के मामले में भी सरकार को ग्रामीण व बंचित वर्ग का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

इन सभी शोध पत्रों से विपरीत प्रावत कुमार जेना ने अपने शोध पत्र "भारत में शिक्षा पर कोरोना महामारी का प्रभाव"International Journal of current research (IJCR)12, 2020 में कोविड-19 के शिक्षा क्षेत्र पर पड़े सकारात्मक परिणामों का विवेचन किया गया। इस शोध पत्र में यह तथ्य उजागर किया गया कि कोरोना महामारी ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य किया है तथा छात्रों को उन नवीन प्रौद्योगिकियों व प्लेटफॉर्मों से परिचित होने का अवसर मिला जिनका पहले कभी उन्होंने उपयोग नहीं किया था। इस शोध पत्र में यह भी कहा गया कि कोरोना वायरस से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद शैक्षणिक संस्थानों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की व वह महामारी के दौरान तकनीकों व उपकरणों के साथ समाज को शिक्षण सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने में कामयाब रहे है तथा इस शोध पत्र में कोरोना काल में सरकार द्वारा निर्बाध शिक्षा प्रदान करने के लिए किए गए उपायों पर भी प्रकाश डाला गया।

मुकेश रावल ने अपने जर्नल "कोविड-19 का भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव का विश्लेषण"(education resorgence journal vol2, issue 5 jan 2021) में कोविड- 19 के भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना पर पड़े सकारात्मक व नकारात्मक दोनो प्रभावों का विश्लेषण किया जिसमें सकारात्मक प्रभाव के रूप में ऑनलाइन शिक्षा के दौरान छात्र अपने समय का अधिक कुशलता से प्रबंधन करने मे सक्षम, विद्यार्थियों को डिजिटल तकनीक सीखने व उपयोग करने के लिए प्रेरणा ,भारतीय शिक्षा प्रणाली का पारंपरिक व्यवस्था से एक नए युग में परिवर्तन आदि को शामिल किया गया जबकि नकारात्मक प्रभाव के रूप में प्रशिक्षण व तकनीक सहायता की कमी, स्पष्टता व दिशा का अभाव, ऑनलाइन मध्यमो की अनुपलब्धता,ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मो के बारे मे सीमित जागरूकता आदि को शामिल किया गया।

कोरोना काल में लड़कियों की शिक्षा पर पड़े प्रभाव को जानने के लिए राइट टू एजुकेशन फोरम ने सेंटर फार बजट एंड पॉलिसी स्टडीज **(CBPS)** व चैंपियंस फॉर गर्ल्स एजूकेशन के साथ मिलकर देश के 5 राज्यों - दिल्ली, असम,बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में 'मेपिंग द

इम्पेक्ट ऑफ कोविड-**19'** नाम से स्टडी की जिसमें यह तथ्य उभरकर सामने आया कि आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के परिवारो की लगभग 70% लड़किया निश्चित नहीं कि वे स्कूल लौट सकेगी। इस अध्ययन में 37% लड़को की तुलना मे महज 26 % लड़कियों ने माना कि उन्हे पढ़ाई के लिए फोन मिल पाता है तथा 56 %लड़को की तुलना में सिर्फ 46% लड़कियो ने माना कि उन्हें पढ़ाई के लिए समय मिल पाता है।

साथ ही प्रोत्साहन इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिल्ली, उत्तराखंड ,ओडिशा, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ में 11-18 वर्ष की लड़कियो के बीच कराए गए सर्वे मे 13% ने कहा कि महामारी के दौरान उनका योन शोषण हुआ। 17 फीसदी ने कहा कि उन्हें अपने आस-पड़ोस में बाल विवाह होने की जानकारी है। 41 फीसदी ने तनाव व अवसाद होने की शिकायत की व 55% बच्चियों ने कहा कि उन्हें कोरोनाकाल में लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ा।

परन्तु वहीं इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस **(UDISE+)** की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में माध्यमिक स्तर के साथ -साथ प्राथमिक कक्षाओं मे स्कूल छोड़ने के मामले में लड़कियो की तुलना में लड़को की संख्या अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार लडकियों की प्राथमिक स्कूल छोडने की दर 1.2%है वहीं लड़को की 1.7% है तथा इसी तरह माध्यमिक कक्षाओ में भी स्कूल छोड़ने की लड़कियो की दर 16.3% जबकि लड़को की दर 18.3% है।

इस प्रकार कोरोना काल में शिक्षा पर पड़े प्रभावों को लेकर विभिन्न शोधकर्ताओं की भिन्न -२ प्रतिक्रियाएं दिखाई देती है।

पाठ - 5

● प्रस्तावित शोध अध्ययन की विधि

1.सम्पूर्ण शोध का माध्यम विशेष रूप से सर्वे को बनाया गया जिसके अंतर्गत बगीची क्षेत्र मे अभिभावको व बच्चो की कोरोना महामारी के दौर में शिक्षा पर पड़े प्रभाव की प्रतिक्रिया को समझने के लिए प्रश्नावली तैयार की गई।यह सर्वे कोरोना काल मे शिक्षा प्राप्त करने में जमीनी स्तर पर आने वाली कठिनाईयों को समझने मे काफी उपयोगी सिद्ध हुआ।

2. इस शोध अध्ययन को करने में वजीरपुर गाँव में प्रत्यक्ष साक्षात्कार को भी आधार बनाया गया। इसके अंतर्गत वजीरपुर गाँव के बच्चों के साथ सीधी बातचीत द्वारा कोरोना काल मे उनकी शिक्षा पर पड़े प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया।

3. इस शोध अध्ययन को करने में विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। हम स्वयं राजनीति विज्ञान की तृतीय वर्ष की छात्राए हैं, महामारी के दौर में विश्वविद्यालय बंद होने के चलते हमारी शिक्षा भी काफी प्रभावित हुई है व हम गूगल मीट, जूम जैसे ऑनलइन माध्यमों से पढाई कर रहे है। ऐसे में इस शोध को करने में व्यक्तिगत रूप से किए गए अनुभव व आस-पास के समाज में पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ।

4. इस शोध अध्ययन में प्रस्तुत डेटा और जानकारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा कोरोना काल में शिक्षा पर पड़े प्रभाव विषय पर प्रकाशित विभिन्न रिपोर्टों और लेखों से एकत्र की गई है। विभिन्न प्रामाणिक वेबसाइटों से भी जानकारी एकत्र की गई है तथा शैक्षणिक प्रणाली पर

कोरोना महामारी के प्रभाव से संबंधित कुछ शोध पत्रों, पुस्तकों व पत्रिकाओं को भी संदर्भ के रूप में उपयोग किया गया है।

पाठ - 6

- ## मुख्य भाग

1.विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर में कमी**-** विद्यार्थी जीवन में प्राचीन के काल से लेकर अब तक एक प्रेरणादाता, मार्गदर्शक व अभिभावक के रूप में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परंतु कोविड-19 के दौर में विद्यार्थी अपने अध्यापको से प्रत्यक्ष संवाद नही कर पाए। इस कारण स्वाभाविक रूप से विद्यार्थियों को अपने अध्यापको से प्रश्न पूछ कर अपनी समस्याओ व जिज्ञासाओं की संतुष्टि करने पर जो ज्ञान प्राप्त होता था, वह कोरोना महामारी के इस दौर में प्राप्त नही हो पाया, साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण इस प्रकार की परिस्थितियाँ उपजी कि या तो छात्रों की परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा या फिर परीक्षाओं के बिना ही उन्हें अगली कक्षाओं मे पदोन्नत करना पड़ा। अभी हाल ही में सी.बी.एस.ई ने भी 10 वी व 12वी कक्षाओं की परीक्षाओ को रद्द कर दिया परंतु यहां मूल सवाल यह है कि कोरोनाकाल की विषम परिस्थितियों में विद्यार्थियों को पदोन्नत करने से वह अगली कक्षाओ मे तो चले जाएंगे परंतु क्या उनके ज्ञान मे पदोन्नति हो पाएगी तथा क्या वो अगली कक्षाओं के ज्ञान को अर्जित करने में सक्षम हो पाएंगे। हमारे सर्वे से यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया कि कोरोनाकाल के चलते बच्चों के ज्ञान में जिस स्तर की फिर वृद्धि होनी चाहिए थी,वह नही हो पाई। कई बच्चों को अपनी पिछली कक्षा की पाठ्यपुस्तकों का नाम तक नही पता था। यहाँ तक कि कुछ विद्यार्थियों ने तो पिछली कक्षाओ की पाठ्यपुस्तकों को खरीदा ही नहीं था। अजीम प्रेम फाउंडेशन द्वारा जनवरी में किया गया अध्ययन भी कोरोनाकाल मे बच्चो के ज्ञान में आई गिरावट को भली भाँति उजागर करता है। इस अध्ययन के मुताबिक पहली से छठी कक्षा के औसतन 92% बच्चों ने पिछले साल के मुकाबले कम से कम एक लैंग्वेज एविलिटी खो दी वही 82% विद्यायलो ने पिछले साल के मुकाबले कम से कम एक मैथमेथिकल एबीलिटी खो दी, इस प्रकार यह अत्यंत चिंतनीय है कि आखिर विद्यार्थी अपने आधे अधूरे ज्ञान के बल पर किस प्रकार अपना व अपने देश का भविष्य उज्जवल कर पाएंगे, हम सभी को गंभीरता पूर्वक इस बारे में चिंतन मनन करने की जरूरत है।

2.अनुशासनविहीन व लक्ष्यविहीन जीवन**-**

(स्रोत - https://gcpawards.com)

हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि एक विद्यार्थी की दैनिक दिनचर्या में विद्यालयों, महाविद्यालयों अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थानों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन शैक्षणिक संस्थानों में ही विद्यार्थी नए-नए गुणों व कौशलों को सीखते हैं तथा अपनी प्रतिभाओं को निखारकर नई-नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। कोरोना महामारी से पहले सामान्य दिनों में विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह-सुबह उठकर नियमित रूप से शैक्षणिक संस्थानों में जाकर ज्ञान अर्जित करते थे साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित होने वाली विभिन्न खेलकूद संबंधी तथा भाषण,कविता गायन, पोस्टर जैसी अन्य पाठ्यतर गतिविधियों में प्रतिभाग करने से उनका शारीरिक, सामाजिक और मानसिक सभी स्तरों पर विकास भी होता था परंतु कोरोना काल में विद्यार्थियों की घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर आने वाली दिनचर्या पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई है । वर्तमान दौर में विद्यार्थी एक अनुशासनविहीन व लक्ष्यविहीन जीवन यापन कर रहे हैं जिसमें उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई अनुशासन या कोई लक्ष्य नहीं रह गया है। अब उनके उठने, पढ़ने, खाने, खेलने का कोई समय निश्चित नहीं है ।इस प्रकार कोविड-19 के दौर में जहां एक ओर विद्यार्थियों की दैनिक समय सारणी बिगड़ गई है वही उसकी पढ़ाई में भी अनियमितता बनी हुई है जोकि किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत गंभीर स्थिति है।

3.ऑनलाइन माध्यमों की अनुपलब्धता - कोविड-19 के दौर में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यमो से निश्चित तौर पर प्रतिदिन लाखों छात्र अपने अध्यापकों से जुड़कर अपनी समस्याओं, आकांक्षाओं व जिज्ञासाओं का समाधान कर पा रहे है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑडियो व वीडियो भेजने के साथ ही गूगल मीट और जूम जैसी ऐपो के माध्यम से कक्षाएं आयोजित कराकर पाठ्य-सामग्री को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लक्ष्मीबाई महाविद्यालय की छात्राओ की भी स्वयं पिछले डेढ़ वर्ष से नियमित रूप से गूगल मीट पर कक्षाएं लग रही है। यहाँ तक कि पिछले वर्ष सी.बी.एस.ई द्वारा दसवी व बारहवी कक्षाओं की अंग्रेजी बोलने की ऑनलाइन कक्षाएं भी आयोजित की गई। इस प्रकार ऑनलाइन माध्यम विद्यार्थियों के जीवन में आई कोरोना रूपी आंधी का मुकाबला करने में मजबूती से उनका सहयोग कर रहे है परंतु ये भी सत्य है ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करने की भी अपनी कुछ सीमाँए है। दूरस्थ स्थानों पर नेटवर्क की अनुपलब्धता, बिजली की समस्या, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर जैसे तकनीकी उपकरणों का अभाव, तकनीकी ज्ञान न होने की स्थिति में ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई बेमानी हो जाती है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम जहाँ एक ओर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा के संसाधन समान रूप से उपलब्ध नहीं है जिसके फलस्वरूप एक बहुत बड़ा विद्यार्थी वर्ग शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित हो रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे के आँकड़े बताते हैं कि देश में केवल 24 % घरों मे ही इंटरनेट की सुविधा है वहीं देश के मात्र 11% घरों ही अपने कम्प्यूटर है। यह चौंकाने वाला तथ्य है कि देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 68% छात्रों की ही ऑनलाइन माध्यमों तक पहुँच है वहीं यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बिहार मे कोरोना महामारी का 75 लाख की शिक्षा पर घातक प्रकार पड़ा है क्योंकि यहाँ सिर्फ 36.5 % छात्रों के पास ही इंटरनेट तथा मात्र 3.5% छात्रों के पास कंप्यूटर की सुविधा है। वास्तव में ऑनलाइन माध्यमो

की अनुपलब्धता के चलते हमारे देश के इस बहुत बड़े विद्यार्थी वर्ग के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना महज एक सपने जैसी है। इसका परिणाम यह निकलता है कि जहाँ इस विद्यार्थी वर्ग मे तनाव व अवसाद को बढ़ावा मिलता है वहीं इसके भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह लग जाता है। इस बात की प्रत्यक्ष साक्षी है केरल जैसी घटनाएं जहाँ एक 14 साल की लड़की ने कोरोना काल में स्मार्टफोन के अभाव में पढ़ाई छूट जाने के कारण आत्महत्या कर ली। यह भी बड़ी विडंबना है कि गांव में बसने वाले हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 15% घरों में ही इंटरनेट की सुविधा है वहीं कंप्यूटर की सुविधा मात्र 4.4% घरों में उपलब्ध है साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट यह तथ्य उजागर करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 47%घर ऐसे हैं जहां 12 या उससे अधिक बिजली रहती है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि बिजली के अभाव के चलते अंधेरे में पढ़कर आखिर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी किस प्रकार अपना भविष्य उज्जवल कर पाएंगे।
शहरी-ग्रामीण ,अमीर-गरीब के इस अंतर को विश्वविद्यालय स्तर पर किए गए सर्वे भी भली-भांति प्रमाणित करते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी द्वारा कराए गए सर्वे में केवल 37% विद्यार्थियों ने कहा कि वह ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते हैं वहीं 90% छात्रों ने कक्षा में लेक्चर लेने को तरजीह देने की बात कही। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच 60 देशों के 470 से अधिक छात्रों ,अभिभावकों व अध्यापकों के लिए गए सर्वे में यह पाया कि महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा पर अत्यधिक निर्भरता ने शिक्षा संबंधी सहायता के मौजूदा असमान वितरण को बढ़ावा दिया है। एक अन्य समस्या यह भी है कि आज डिजिटल होती दुनिया के बीच तकनीक पर खर्च भी बढ़ रहा है। ब्रिटेन में हुए एक शोध के अनुसार जब तक बच्चा 16 वर्ष की उम्र तक पहुंचता है तब तक माता-पिता को तकनीक पर ₹4,0000 से अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है जबकि 2 साल पहले तक यह राशि ₹10,000 के आसपास थी ।इस प्रकार हम देखते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है साथ ही ऑनलाइन शिक्षा इसलिए भी बेमानी हो जाती है क्योंकि यह बात तो किसी से छिपी नहीं है कि कितने घंटे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तथा कितने घंटे पब्जी और फ्री फायर जैसे गेम खेलने या चैटिंग करने में व्यर्थ कर देते हैं। हमारे द्वारा किए गए सर्वे में भी यह बात उभरकर सामने आई कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान बच्चे गूगल मीट पर अपनी कक्षाएं शुरू कर या तो मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर खेलने चले जाते हैं या वह ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। इस प्रकार कोरोना महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण सुविधाओं के अभाव के कारण विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी होने के बावजूद भी पूर्ण रूप से जारी नहीं है।

4.बच्चों का स्कूली शिक्षा से बिछड़ना-

(स्रोत- www.bhasker.com)

आज हम सब सभी एक ऐसे काल में जी रहे हैं जहां बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, लोगों की तनख्वाह घट रही है,लोगों की जेब में पैसा नहीं है। ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का कार्य कर रही है। यह तथ्य भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि इस कोरोना वायरस सबसे ज्यादा मार हमारे देश में निवास करने वाले 52 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों को ही झेलनी पड़ी। शहरों में रोजगार का कोई स्त्रोत ना रहने पर व सिकुड़ते आय के साधनों के बीच इन दिहाड़ी मजदूरो को शहर से गांव की ओर एक दर्द भरा प्रवासन करना पड़ा। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए उनके बच्चे जो गांवों में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके तथा विद्यालयों को उनका नामांकन रद्द करना पड़ा। हमारे सर्वे में भी यह समस्या स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई कि कोरोना काल में अपने गांव चले जाने के कारण बच्चों का स्कूल से नाम कट गया तथा शहरों में वापस आकर भी दाखिले के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र गांवों में ही छूट जाने के कारण उनका किसी भी विद्यालय में नामांकन नहीं हो पाया साथ ही कोरोनाकाल से उपजी विषम परिस्थितियों के बीच कई माता-पिता अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा करने कराने में भी सक्षम नहीं रहे। कानपुर नगर में किया गया एक सर्वे बताता है कि इस नगर में मात्र 10 फीसदी ऐसे विद्यालय जहां 70 या अधिक अभिभावकों ने फीस जमा करा दी 20 फीसदी ऐसे स्कूल है जिनमें 50 फीसदी अभिभावक ने फीस जमा करवा दी वहीं शहर के 70 फीसदी ऐसे विद्यालय हैं जहां 30 फीसदी या इससे कम अभिभावक की फीस जमा करा पाए। फीस जमा कराने की असमर्थता के कारण ही माता पिता के पास अपने बच्चों को शिक्षा से ड्रॉपआउट करवाने या उनका प्राइवेट विद्यालय से सरकारी विद्यालय में स्थानांतरण करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस **(UDISE+)** की रिपोर्ट बताती है कि देश में बच्चों की माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की कुल दर 17.3% है। देश की राजधानी दिल्ली में ड्रॉपआउट दर 20% से अधिक तो वही असम, अरूणाचल प्रदेश में 25% से अधिक ड्रॉपआउट दर है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो जहां एक और यहां 60,253 बच्चों ने ड्रॉप्डआउट किया वहीं दूसरी ओर पिछले 1 साल में करीब 2 लाख बच्चे प्राइवेट विद्यालय को छोड़कर सरकारी विद्यालय में भर्ती हुए। देश के समृद्ध राज्य में गिने जाने वाले हरियाणा में भी पिछले वर्ष निजी विद्यालय में भर्ती छात्रों की संख्या 90 लाख 83 हजार थी जो अब घटकर मात्र 17 लाख रह गई है। यह भी अत्यंत चिंताजनक है कि ड्रॉपआउट करने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या अधिक रही है। राइस टू एजुकेशन फोरम का कहना है कि इस वर्ष 1 करोड़ लड़कियों ने माध्यमिक विद्यालय से ड्रॉपआउट किया। इस प्रकार मेरा यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश के अनेक मासूम बच्चों का कीमती 1 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गया। ऐसे में अब जब धीरे-धीरे विद्यालय खुलने लगे हैं तो इन बच्चों की वापसी सुनिश्चित करना व इन्हें विद्यालय में बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है जिसका सामना करने की इच्छाशक्ति की हमारे बच्चों के भविष्य का पथ निर्धारित करेगी

5. लैंगिक असमानता

इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि चाहे जंग हो या महामारी इसके सबसे बुरे परिणाम लड़कियों को ही झेलने पड़ते हैं। साल 2004 में अफ्रीकन देशों में फैली इबोला महामारी के समय

में भी ऐसा ही दिखाई दिया। वहां लड़कों के मुकाबले लड़कियों के विद्यालय ज्यादा जल्दी छूटे जिसके लड़कियों की जल्दी शादियां होना तथा कम उम्र में मां बनने जैसे दुष्परिणाम सामने आए। अब कोरोना काल में भी वर्चुअल पढ़ाई के दौरान लड़कियों को ही दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ तो घरों में लड़कियों पर घरेलू काम का बोझ उन्हें शारीरिक तथा मानसिक तौर पर थका देता है वहीं दूसरी तरफ मोबाइल फोन की पहुंच न होने की वजह से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने का मौका भी उनके हाथ नहीं लग पाता है। इंटरनेट तथा मोबाइल एसोसिएशन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 67 प्रतिशत पुरुष जबकि मात्र 33 प्रतिशत महिलाएं ही इंटरनेट का उपयोग करती हैं। ग्रामीण भारत में यह अनुपात और अधिक असंतुलित है। वहां पुरुषों की तुलना में महज 28% महिलाओं की ही इंटरनेट तक पहुंच है। इस प्रकार कोरोनावायरस के दौर में वर्चुअल पढ़ाई के कारण लड़के-लडकियो के बीच अंतर ओर अधिक गहरा गया है जिसे डिजिटल डिवाइड कहा जा सकता है साथ ही कोरोना काल से आर्थिक संकट के बीच लड़कियों का विद्यालयों से ड्रॉपआउट करने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में सरकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को लड़कियों की पढ़ाई तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि हमारे देश की आधी आबादी अपनी प्रतिभाओं व योग्यताओं को निखारकर राष्ट्र के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे सकें।

6.बाल विवाह**-** महामारी के कारण देश के लगभग सभी राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तबके में बाल विवाह के मामले बढ़े हैं जोकि समाज के लिए काफी खतरनाक है। यूनाइटेड नेशन पापुलेशन फंड का अनुमान है कि आने वाले 10 वर्षों में 13 मिलीयन से भी ज्यादा लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाएगी। राइट टू इनफार्मेशन फोरम ने भी अपनी स्टडी में पाया कि किशोरावस्था की लगभग 37% लड़कियां इस बात पर निश्चित नहीं कि वह विघालय लौट सकेंगी इसका एक कारण बाल विवाह है। बाल विवाह की घटनाओं में अभूतपूर्व बढ़ोतरी गरीबी ,असुरक्षा, लैंगिक असमानता, कानूनों का पूरी तरह पालन ना होने, अभिभावकों में जागरूकता की कमी आदि से हुई है। महामारी के दौरान कामकाज बंद होने कि स्थिति में मां-बाप सोचते हैं कि बेटियों की शादी कर दी जाए। इससे बेटियों के पालन- पोषण पर होने वाले खर्च से भी बच जाएंगे लेकिन इसका उन मासूम लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा इस बात से बेखबर होते हैं।कम उम्र में शादी की वजह से आज भी हमारे देश में अनेक लड़कियां शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो जाती हैं, उनका बचपन उनसे छिन जाता है, कम उम्र में गर्भधारण से लड़की के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है साथ ही उनकी यौन शोषण व घरेलू हिंसा का जोखिम भी बढ़ जाता है ।

बाल विवाह नाम की समस्या की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक RTI के जरिए मिले आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को हेल्पलाइन नंबर 1098 पर साल 2020 मैं अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक बाल विवाह से जुड़े 18,324 कॉल मिले।

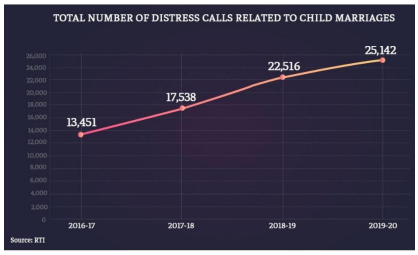

(स्रोत - RTI)

हालांकि इस कुप्रथा के शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं जैसे महिला एवं बाल कल्याण विभाग में ने महामारी के दौरान 1355 बाल विवाह रोके, उड़ीसा राज्य ने यूनिसेफ के साथ मिलकर राज्यव्यापी अभियान चलाया है अभी हमें ऐसे ही सतत प्रयासों की जरूरत है ताकि बच्चों का उच्च शिक्षा,अच्छे भविष्य का सपना अधूरा ना रह जाए।

7.बाल मज़दूरी-एक अभिशाप - हमारे लिए बचपन का मतलब है हँसना, खेलना- कूदना और पढ़ना। पर क्या सभी के लिए बचपन का यही मतलब है? **ILO**और **UNICEF** की रिपोर्ट बताती है कि पिछले २० सालों में पहली बाल-मज़दूरो की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का हर दसवां बच्चा किसी न किसी तरह की मजदूरी करने को मजबूर है। चार साल पहले करीब 15 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते थे, यह संख्या अब बढ़कर 16 करोड़ हो गई है।

यदि बात भारतीय परिप्रेक्ष्य की करें तो भारत में 5-9 साल के कुल बच्चों में से 25.33 लाख बच्चे काम करते हैं तथा 10-14 उम्र के 75.95 लाख बच्चे कामगर हैं। इन आंकड़ों के पीछे कारण बिलकुल साफ है। महामारी से उपजे आर्थिक संकट, बेरोजगारी पलायन, स्कूल बंदी, माता -पिता की मृत्यु आदि से बाल श्रम में भारी इजाफा हुआ है। करोड़ो बच्चे कक्षाओं में वापिस न लैटकर बाल मज़दूरो की जमात में शामिल होने को विवश हुए हैं। बाल श्रम नामक यह मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, विशेषज्ञों का मानना है कि सामान्य स्थिति बहाल होने पर भी यह बच्चे अपनी शिक्षा ज़ारी नहीं रख सकेंगे। यानि यह एक दीर्घकालिक व गंभीर आपदा है। इससे जहाँ एक तरक विधार्थियों के शारीरिक, मानसिक व यौन शोषण की संभावना बढ़ी है वहीं यह हमारे बच्चों के भविष्य को भी संक्रमित कर रहा है।

यदि पूरा विश्व समुदाय एकजुट होकर बच्चो का बचपन बचाने के लिए गहरी संवेदनशीलता नहीं दिखाता तो हम एक पीढ़ी के भविष्य की बर्बादी के गुनहगार होंगे। ज़रूरत है कि स्थानीय इकाइयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिनमें इन सभी आयामों का समन्वय हो।

8.पढ़ाई से वंचित दिव्यांग छात्र-

(स्रोत- दैनिक भास्कर)

पूर्व स्वास्थ्य अपात्काल योगदान में दिव्यांगों पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव डाला है। देश के 7 राज्यों के 90,609 से अधिक मूक- बधिर बच्चे कोरोना महामारी की वजह से पिछले 16 महीने से पढ़ाई से पूरी तरह वंचित हैं क्योंकि इनके स्कूल व छात्रावास बंद हैं। देश में सामान्य बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास तो चल रही हैं लेकिन इन विद्यार्थियों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। न तो इनके पास अपनी आवश्यकता के मुताबिक मोबाइल फोन है ना ही ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रशिक्षित शिक्षक। यहां तक कि केंद्र सरकार का ई विद्या पोर्टल भी इनकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है। 44 फीसदी दिव्यांग बच्चों की शिकायत है कि वेबीनार और ऑनलाइन शिक्षा में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर न होने के कारण उन्हें समझने में दिक्कत आ रही है, नेत्रहीन दिव्यांग बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान की उनकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है जो कि पहले स्कूल में हो जाती थी।
इस गंभीर स्थिति को समग्र रूप में इस प्रकार से भी जा सकता है कि देश भर में 2.6 करोड़ दिव्यांग हैं जिनमें से 45% यानी 1.1 करोड़ निरक्षर हैं। भास्कर की पड़ताल के मुताबिक राजस्थान में मुक बधिरो के लिए संचालित स्कूलों में 1100, छत्तीसगढ़ में 4625, बिहार में 2500, झारखंड में 2200, यूपी में 70,000, मध्यप्रदेश में करीब 5,500 की पढ़ाई पूरी तरह ठप है। साथ ही मध्य प्रदेश में तो इन विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए बने 68 हॉस्टल पूरी तरह बंद हैं।

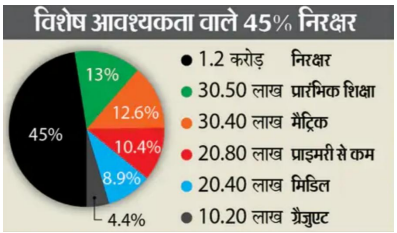

(स्रोत- दैनिक भास्कर)

विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते अगर इनकी शिक्षा को लेकर कदम नहीं उठाए गए तो इन में निरक्षरता की दर 75% तक बढ़ सकती है।

इन बच्चों को कोरोना के शिक्षा पर पड़े भयंकर प्रभावों से बचाने के लिए कुछ सराहनीय प्रयास भी किए गए हैं।जैसे कि राजस्थान सरकार द्वारा मिशन समर्थ के तहत पहली से बारहवीं तक के छात्रों के लिए वीडियो लाइब्रेरी एवं साइन लैंग्वेज के रूप में सिलेबस तैयार किया गया है तथा यह तय किया गया है बच्चों को ब्रेल लिपि में ही वर्कशीट दी जाएं। बुरहानपुर शहर में चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित मूक बधिर, दिव्यांग विद्यालय के शिक्षक- शिक्षिकाओं ने वर्तमान में पढ़ाई से वंचित हो रहे विद्यार्थियों को घर-घर जाकर पढ़ाया। कुछ चुनौतियां इन प्रयासों की आती हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ में इन बच्चों के लिए विजुअल कोर्स तो बनाया गया लेकिन ज्यादातर बच्चों के पास मोबाइल फोन न होने व ठीक से दिखाई न देने के कारण इसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। यानी कि विशेष बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी समग्र शिक्षा की दिशा में नवीन अविष्कारों की आवश्यकता है विद्यार्थियों का यह वर्ग भी इस मुश्किल दौर में अपनी पढ़ाई को जारी रख सके।

9. कुपोषण-

(स्रोत - https://www.hrw.org)

स्वास्थ्य आपातकाल के कारण घोषित लॉकडाउन के चलते पिछले15 महीनों में बच्चे स्कूल से मिलने वाले एक वक्त के माध्याह भोजन और आयरन फोलिक एसिड की नियमित खुराक से भी वंचित हो गए हैं। इससे कुपोषण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही के इस समय घर में उत्पन्न हुई आर्थिक मंदी, पोषण सेवाओं व आपूर्ति श्रंखला के टूटने तथा विद्यार्थियों के संक्रमित होने से भी बच्चों की आहार गुणवत्ता में गिरावट और कुपोषण मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मैपिंग द इंपैक्ट ऑफ़ कोविड**-19** नाम से उत्तर प्रदेश, बिहार असम ,दिल्ली में 3176 परिवारों पर किए गए अध्ययन में 70% लोगों ने माना कि उनके पास खाने को भी पर्याप्त नहीं बचा है। यह बहुत विकट स्थिति है।

यूनिसेफ के अनुसार महामारी के बाद वेस्टिंग से ग्रस्त बच्चों की संख्या साल भर में बढ़कर 4 मिलियन हो जाएगी तथा कुपोषण बढ़ने से हर महीने 10,000 से अधिक बच्चों की मृत्यु होगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे ने भी बताया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में विकास न होने की समस्या 38.4% प्रतिशत है, उम्र के अनुपात में वजन की समस्या 35.8%है।

कुपोषण से बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास, उनका इम्यून सिस्टम प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से लड़कियों के संदर्भ में कुपोषण की समस्या को रेखांकित करते हुए यह बताना आवश्यक है इससे लड़कियों में एनीमिया का खतरा बढ़ गया है। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर ने देश के 36 शहरों में एक सर्वे किया व पाया कि 15- 48 साल की 10 में से हर 6 महिलाएं अलग-अलग

स्तर पर एनीमिया का शिकार हैं। कुपोषण भयंकर समस्या से बच्चों की शिक्षा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है।यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि कुपोषण के कारण बीमारियों से ग्रसित यह बच्चे अपनी पढ़ाई में जंतर तो रख पाएंगे?
हालांकि यहां इस समस्या से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन भी आवश्यक हो जाता है समेकित बाल विकास सेवा के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को पूरक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराए जा रहे हैं ,वहीं सरकार ने भी 4 महीने तक राशन धारक परिवारों को निशुल्क अनाज देने की घोषणा की है,महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई।
ऐसे ही कुछ अन्य प्रयासों की आज हमें दरकार है क्योंकि स्वस्थ विद्यार्थी ही शिक्षित, मजबूत व प्रगतिशील भारत के निर्माण की नींव होते हैं।

10. स्वास्थ्य - स्कूल बंदी से बच्चे व्यायाम,योग, खेलकूद व अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पा रहे हैं और वह परीक्षाओं का भय, अध्यापकों, दोस्तों से आमने सामने न मिलने की परेशानी को भी झेल रहे हैं। इससे इतर परिवार की आर्थिक तंगी व माता-पिता के झगड़े भी उनमें अकेले पन का भाव पैदा करते हैं। यानी कि कोरोना का बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा है।
स्कूल बंदी के बाद ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया बल्कि इसने तो ओर तरीके के प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर डालने शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन संसाधनों की अनुपलब्धता से विद्यार्थी तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। इस बात को प्रमाणित करने की इससे बड़ी घटना ओर क्या होगी कि पिछले साल दक्षिणी केरल में एक 14 साल की बच्ची ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए मोबाइल फोन नहीं था। वही ऑनलाइन सुविधाओं तक पहुंच रखने वाले छात्रों में समाजिक जुड़ाव व नियमित दिनचर्या के अभाव में मोबाइल फोन व टीवी की ओर झुकाव बढ़ा है। इससे उनकी आंखों में परेशानी, जलन,चिड़चिड़ापन, सिर में दर्द जैसी विसंगतियां उभर कर सामने आ रही हैं। ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों का स्लीपिंग पैटर्न भी बिगड़ जाता है, वह पूरी तरह नींद नहीं ले पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज में विद्यार्थी अपने अध्यापक- अध्यापिकाओं से सहज रूप में बात नहीं कर पाते, कुछ विद्यार्थी पूरे दिन होमवर्क के बोझ तले दबे रहते हैं जिसकी वजह से उनमें डिप्रेशन का खतरा है।इसकी गंभीरता का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली स्थित स्कूल के 12वीं के एक छात्र ने स्कूल खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इनका मानना है कि क्लासेस में विद्यार्थी मानसिक व शारीरिक पीड़ा से गुजरने को मजबूर हैं। यदि हम अन्य आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि महामारी के दौरान 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों में मानसिक बीमारियों से ग्रस्त बच्चों की संख्या 5.1 प्रतिशत बढ़ गई है जबकि 11 से 16 साल की उम्र में ऐसे बच्चों की संख्या में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।एम्स दिल्ली द्वारा 22,956 बच्चों पर शोध किया गया जिसके अनुसार कोरोना वायरस के दौरान 34.5 बच्चों में घबराहट और एंजाइटी के लक्षण दिखे, 41.7 प्रतिशत बच्चों को डिप्रेशन हो गया, 30.8 प्रतिशत बच्चों का व्यवहार पहले से बदल गया है अब वह हर चीज में आनाकानी करने लगे हैं। स्वास्थ्य पर कोविड के प्रभावों को

देखते हुए बच्चों की काउंसलिंग करने, उनके अकेलेपन को दूर करने की जरूरत है। साथ ही स्कूल बंदी के दौरान विद्यार्थियों के पास उपलब्ध इस खाली समय को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने की भी आवश्यकता है जिससे कि वह अपनी रूचियों, प्रतिभाओं को विकसित कर सकें तथा किसी भी प्रकार के मानसिक व शारीरिक विकार से बच सकें।

पाठ-7

- आंकड़ों का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा परिणाम

बगीची क्षेत्र में लिए गए सर्वे के परिणामो का विश्लेषण -

छात्रों के लिए सर्वेक्षण की प्रश्नोत्तरी

Q1 आप वर्तमान समय मे किस माध्यम से पढ़ाई कर रहे है?
a) व्हाटसप b) गूगल मीट c) जूम d) इनमे से कोई नही

Q2 आप ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान इनमे से कौन-सी स्वास्थ्यगत समस्या को महसूस करते है?
a) आँखो मे परेशानी b) सिर मे दर्द
c) अवसाद, चिंता या नींद न आना d) उपरोक्त सभी

Q3 आप किस माध्यम से ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाते है
a) ऑफलाइन माध्यम b) ऑनलाइन माध्यम

Q4 कोरोनामहामारी के दौरान शिक्षा प्राप्त करने मे आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा?
a) मोबाइल फोन की अनुपलब्धता b) भाई बहनो के लिए एक ही मोबाइल
c) नेटवर्क समस्या d) इनमे से कोई नही

Q5 ऑनलाइन पढ़ाई के क्या लाभ है?
a) तकनीकी समझ मे बढ़ोतरी b) स्वस्थ पारिवारिक संबंध
c) समय व धन की बचत d) कोरोना से बचाव

Q6 आप ऑनलाइन पढ़ाई मे किस चीज को बहुत मिस कर रहे है?
a) अध्यापको के स्नेह को b) क्लासरूम मे बैठकर पढ़ाई करने को
c) दोस्तो के साथ खेलने को d) इनमे से कोई नही।

नाम → आयु → लिंग → शैक्षिक योग्यता →

अभिभावकों के लिए सर्वेक्षण की प्रश्नोत्तरी

Q1 आपके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान इनमें से कौन-सी स्वास्थ्यगत समस्या का सामना कर रहे हैं?

a) आँखों में परेशानी
b) सिर में दर्द
c) अवसाद, चिंता या नींद न आना
d) उपरोक्त सभी

Q2 आपके अनुसार किस माध्यम से छात्रों की ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़ाई हो पाती है?

a) ऑनलाइन माध्यम
b) ऑफलाइन माध्यम

Q3 महामारी के समय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपके बच्चों को किन परेशानियों ~~का सामना~~ से गुजरना पड़ा?

a) मोबाइल फोन न होना
b) भाई-बहनों के लिए एक ही मोबाइल
c) नेटवर्क समस्या
d) इनमें से कोई नहीं

Q4 कोरोना काल में लड़के-लड़कियों की शिक्षा किस रूप में प्रभावित हुई है?

a) लड़कों की ज्यादा प्रभावित हुई
b) लड़कियों की ज्यादा प्रभावित हुई
c) दोनों पर समान प्रभाव पड़ा
d) दोनों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा

Q5 आपके अनुसार क्या विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में पदोन्नत करने का निर्णय सही था?

a) हाँ
b) नहीं

Q6 आपका क्या विचार है स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं?

a) हाँ
b) नहीं

Q7 आप वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए पढ़ाई के बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे?

a) क्रमबद्ध तरीके से विद्यालय खोले जाएं
b) सभी बच्चों की इंटरनेट तक पहुँच सुनिश्चित की जाए
c) ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यमों में बदलाव हो।
d) बच्चों को रचनात्मक ढंग से पढ़ाया जाए।

- विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप को अपनी पढ़ाई के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना।उन्होंने दूसरी वरीयता गूगल मीट को दी।

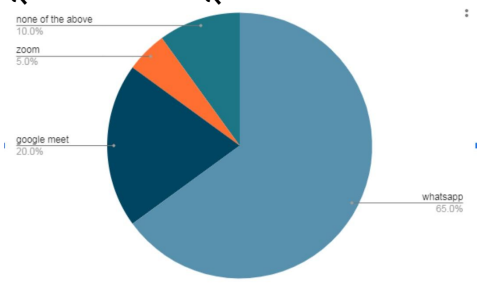

- विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पठन-पाठन के दौरान आंखों में परेशानी, सिर में दर्द या चिंता, तनाव को एक साथ महसूस किया।ऐसे विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 70% रही। साथ ही बच्चों के माता-पिता ने भी ऑनलाइन शिक्षा के अपने बच्चों पर पड़ने वाले स्वास्थ्यगत प्रभावो के विषय में चिंता व्यक्त की।

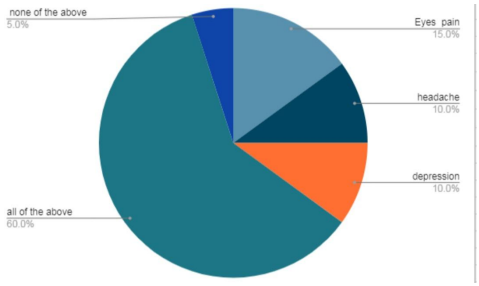

- अधिकांश विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई के लिए ऑफलाइन माध्यम को बेहतर माना उनके पेरेंट्स ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की। साथ ही वजीरपुर गांव में लिए गए प्रत्यक्ष वार्तालाप में भी छात्रों
  ने ऑनलाइन पढ़ाई में कम समझ आने की शिकायत की।
- बगीची क्षेत्र में हमें विद्यालयी जगत में मोजूद आर्थिक असमानता की गंभीरता का भी एहसास हुआ। यहां 40% छात्रों ने मोबाइल फोन तक पहुंच को अनुपलब्ध बताया तथा 39% छात्रों ने भाई बहनों के पास एक ही मोबाइल फोन की समस्या को अपनी पढ़ाई में सबसे बड़ी रुकावट माना।जबकि मात्र 5%छात्रों में इस तरह की किसी समस्या के न होने की बात कही।

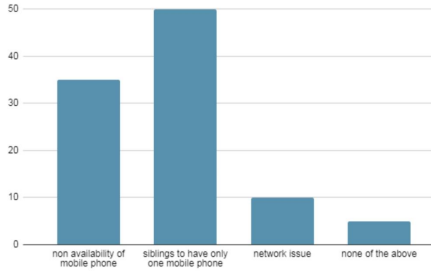

- सच्चाई का एक अंश यह भी है कि अधिकतर छात्रों ने कोरोना से बचाव के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर माना। छात्रों ने इसे पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने तथा तकनीकी समझ में बढ़ोतरी के लिए भी फायदेमंद बताया।

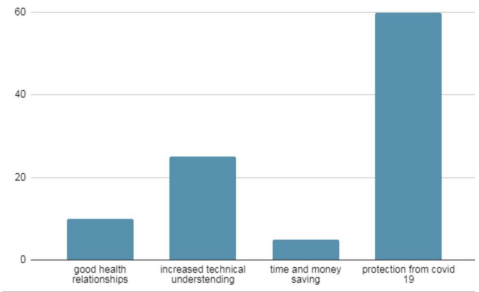

- बच्चों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के दौरान अपने अध्यापकों तथा अपनी पढ़ाई को सबसे अधिक याद किया गया। जो हमें इस कठिन समय में अध्यापकों की प्रासंगिकता प्रकाश डालता है तथा इस दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका का बोध कराता है।
- इस सर्वे में हमे शिक्षा बनाम स्वास्थ्य के विवाद का हल होता हुआ भी नजर आता है। अधिकतर माता-पिता ने माना कि कोविड संबंधी व्यवहार का पालन करते हुए स्कूल खोले जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन शिक्षण प्रदति के दोषों को कम करने के लिए ऑनलाइन माध्यमों में कुछ सुधार तथा सभी तक इंटरनेट की पहुंच को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। रेखांकित किया।

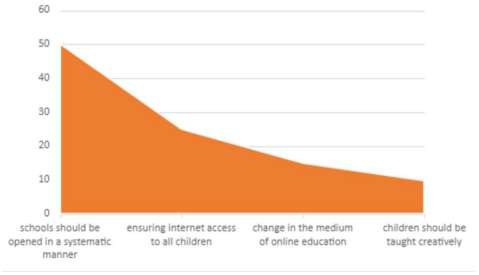

शोध में प्रयुक्त अन्य आंकड़ों का विश्लेषण-

- यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान निम्न आय वाले देशों में प्राथमिक स्तर पर तकरीबन 86% छात्र स्कूली शिक्षा से बाहर हो गए, जबकि उस आय वाले देशों में यह आंकड़ा केवल 20% है। यह रिपोर्ट हमें इस वैश्विक आपदा के समय शैक्षणिक क्षेत्र में मौजूदा असमानता को खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता को बताता है।
- नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि देश में केवल 14% घरों में ही इंटरनेट की सुविधा है। वही दूसरों में बच्चों के पास कंप्यूटर है। यह आंकड़ा ऑनलाइन शिक्षा को ऑफलाइन शिक्षा के विकल्प के रूप में पेश करने पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। व विद्यार्थियों तक इंटरनेट की सीमित पहुंच को उजागर करता है।
- संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस की रिपोर्ट बताती है कि माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की अंदर 17.3 प्रतिशत है। यह आंकड़ा विधार्थियों द्वारा स्कूल शिक्षा से बिछड़ने की गंभीरता को दर्शाता है। साथ ही बच्चों की स्कूली शिक्षा में वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए हमें चेताता है।

- आईएलओ यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि 20 सालों में पहली बार बाल मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का हर बच्चा कहां के मजदूरी करने को मजबूर है। विद्यार्थियों पर पड़ने वाले एक दीर्घकालिक प्रभाव को भी स्पष्ट करता है और साथ में इस बात की अनिश्चितता को भी दर्शाता है कि स्कूली शिक्षा में वापस लौट पाएंगे या नहीं।
- एक आरटीआई के जरिए मिले आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर साल 2020 में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक बाल विवाह से जुड़े 18,324 को मिले। यह दर्शाता है कि लड़कियों की शिक्षा पर कोरोना की अधिक मार पड़ी है अौर यह आंकड़ा माता-पिता में अपने बेटियों के भविष्य को लेकर एक प्रकार की असुरक्षा को भी उजागर करता है।
- एम्स दिल्ली द्वारा 22,993 बच्चों पर शोध किया गया जिसके अनुसार महामारी के दौरान 34.5% बच्चों में और एंजाइटी के लक्षण दिखे तथा 41% प्रतिशत बच्चों को डिप्रेशन हुआ। यह बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े प्रभाव को दर्शाता है।

पाठ-8

- निष्कर्ष

हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में छात्रों की शिक्षा काफी प्रभावित हुई है ।आज हम परंपरागत शिक्षा प्रणाली की जगह शैक्षिक प्रौद्योगिकी मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं ।शिक्षा के इस नए मॉडल में जहां एक और बहुत बड़ा विद्यार्थी वर्ग तकनीकी उपकरणों के अभाव के कारण ऑनलाइन शिक्षण सुविधाओं से वंचित हो रहा है वहीं दूसरी ओर शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम छात्र भी अपने अध्यापकों व मित्रों के साहचर्य के अभाव में नीरस व तनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं परंतु इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर कर इन कमियों को दूर करने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान किया है वास्तव में इस समय हमारा उद्देश्य मात्र महामारी से पहले की स्थिति बहाल करना नहीं होना चाहिए अभी तो शिक्षा प्रणाली की उन खामियों को दूर करना भी होना चाहिए जिनके कारण लंबे समय से विद्यार्थी के एक वर्ग के लिए विद्यालयों के द्वार नहीं खुल पाए हैं ।ह्यूमन राइट्स वॉच का यह कहना है कि सरकार को चाहिए कि 2030 तक सभी बच्चों के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्ति की गारंटी करने वाले संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के तहत 2015 में की गई अपनी प्रतिबद्धताओं पर तुरंत अमल करें ।इसके लिए सर्वप्रथम सभी सरकारों ,सामाजिक कार्यकर्ताओं और इस दिशा में कार्यरत सभी संस्थाओं को समावेशी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति होनी चाहिए तथा उन्हें कोरोना काल में पढ़ाई छूटने के खतरे का सबसे ज्यादा सामना कर रहे बच्चों की स्कूल वापसी पर सबसे पूरा जोर लगाना चाहिए तथा विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को विद्यालयों में वापसी लाने के लिए उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जानी अत्यंत आवश्यक है साथ ही अगर कोरोना काल में बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं बच्चों तक पहुंच जाए जाए अर्थात लाभार्थी परिवारों तक राशन ,सैनिटरी नैपकिन

तथा आवश्यक पोषण की दवाइयां घरों तक उपलब्ध कराए जाएं साथ ही पाठ्य सामग्री भी नियमित अंतराल पर बच्चों तक पहुंचाई जाए ताकि ऑनलाइन शिक्षा से वंचित छात्र भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। प्रवासी मजदूरों के बच्चों तक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है इसके लिए इस शैक्षणिक सत्र में नामांकन को लेकर आवश्यक कागज व समय सीमा में लचीलापन रखना चाहिए तथा राज्य के बोर्ड आपस में सहयोग करें जिससे गांव में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरो के बच्चों को भी शिक्षा मिल सके ।इसके अलावा मजबूत शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त निवेश व संसाधनों का समान वितरण किया जाए ,भेदभावपूर्ण नीतियां व कार्यप्रणाली को हटाया जाए तथा सभी छात्रों को सबसे भरोसेमंद ,सस्ती व सुलभ इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाए परंतु यह भी तथ्य है कि डिजिटल पढ़ाई को ही कोरोना काल में शिक्षा का एकमात्र माध्यम नहीं बनाया जा सकता ।वर्तमान समय में जब कोरोना का संक्रमण काम हो रहा है तो विद्यालयों को चरणबद्ध ढंग से खोले जाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 21 राज्यो के 70 जिलों में कराए गए चौथे सीरो प्रीवेलेंस सर्वे में 6 से 9 वर्ष के छात्रों में 57.2 प्रतिशत तथा 10 से 17 वर्ष के छात्रों में 61. 6 प्रतिशत सीरो प्रीवेलेंस पाया गया इसी को देखते हुए आईसीएमआर के निदेशक डॉ बलराम भार्गव जी ने सुझाव दिया कि आधे से अधिक बच्चों के शरीर में एंटीबॉडी बन गई है इसलिए विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलना सुरक्षित है परंतु विद्यालय खोलने से पूर्व शिक्षकों व स्टाफ का टीकाकरण होना आवश्यक है बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य होना चाहिए व कमरे का वेंटीलेशन भी अच्छा होना चाहिए साथ ही यह भी आवश्यक है कि केंद्र व राज्य सरकारें ट्रिगर प्वाइंट तय करें अर्थात जैसी परिस्थिती हो उसके अनुसार फैसले लिए जाएं। इसके लिए राज्य स्तर पर आपातकालीन शिक्षण समिति का गठन किया जाए जो कोरोना के प्रभाव का आकलन करने के पश्चात इसके अनुरूप रणनीति तैयार करें। इन सभी सुझावों से बढ़कर वर्तमान समय में जब बच्चों के भविष्य के समक्ष अब तक का सबसे गंभीर खतरा विघमान हैं तो आवश्यक है कि संपूर्ण विश्व समुदाय एकजुट होकर बच्चों का बचपन बचाने के लिए गहरी संवेदनशीलता के साथ कठोर कदम उठाए तभी हम एक पूरी पीढ़ी के भविष्य की बर्बादी को रोक पाएंगे।

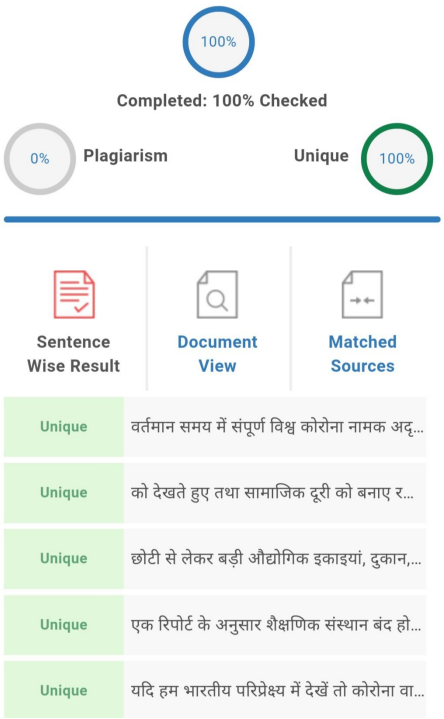

संदर्भ सूची-

- दैनिक भास्कर का कोरोना की वजह से पढ़ाई से वंचित मुक - बधिर छात्र नामक लेख।
- दैनिक भास्कर का प्राइमरी स्कूल खोलने की सलाह नामक लेख
- https://www.naidunia.com
- https://www.hrw.org
- https://www-tv9hindi-com
- https://www.drishtiias.com
- https://www.gaonconnection.com
- hindi.news18.com
- https://inbreakthrough.org
- https://www.amarujala.com
- https://downtoearth.org.in
- https://www.unicef.org.in
- htttps://navbharat.indiatimes.com
- https://m.economictimes.com
- www.bbc.com
- www.zeebiz.com